भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5138

24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित कृषि योजनाएँ

5138. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान में कार्यान्वित सभी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्षवार/योजनावार/और आंध्र प्रदेश में विशेषकर कोनासीमा जिले सहित जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान निर्धारित भौतिक लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का वर्षवार/योजनावार और आंध्र प्रदेश में विशेषकर कोनासीमा जिले सहित जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्षवार/योजनावार और आंध्र प्रदेश में विशेषकर कोनासीमा जिले सहित जिलावार संख्या कितनी है;

(ङ) केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तथा विशेषकर कोनासीमा जिले से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति की स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में, विशेषकर कोनासीमा जिले में, कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि सहित

कृषि के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश सहित संपूर्ण देश में कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध -II** में दिया गया है। जिला-वार वास्तविक लक्ष्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और मॉनीटर किए जाते हैं, तथापि, योजना-वार वास्तविक प्रगति का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत, लाभार्थी डेटा को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ): राज्य सरकारें वार्षिक कार्य योजनाओं के रूप में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। इन योजनाओं को योजना दिशानिर्देशों, धन की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विभिन्न जिलों से संबंधित प्रस्तावों पर राज्य की समग्र योजना के भाग के रूप में विचार किया जाता है और अनुमोदन स्तर पर जिला स्तर के लिए अलग से चिह्नित नहीं किया जाता है।

(च): सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित देश भर में कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और किसानों तक पहुंच में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विस्तार सेवाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण, लक्षित वितरण और रियल टाइम परामर्श के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग, लास्ट माइल वितरण संस्थानों को सुदृढ़ करना, मशीनीकरण और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का सहयोग और किसानों को वित्तीय सहायता और रियायती ऋण का प्रावधान शामिल है।

अनुबंध I

कृषि में राज्यों की सहायता के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसन)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. प्रधान मंत्री अन्नदता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
10. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
12. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

अनुबंध II

आंध्र प्रदेश के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2022-23 से 2024-25 तक कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	**मिशन/योजना का नाम**	**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		
क	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**	**आवंटन**	**रिलीज**	**व्यय**	**आवंटन**	**रिलीज**	**व्यय**	**आवंटन**	**रिलीज**	**व्यय**
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-डीपीआर	183.2	45.79	42.48	86.33	86.33	86.33	86.33	63.75	63.75
2	कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	75.00	47.45	47.45	51	-	-	50.99	46.65	46.65
3	पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)	300	222.82	222.82	230	105.75	105.75	352	239.9	239.9
4	सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी	4.37	-	-	9.52	4.2	4.2	8.81	6.45	6.45
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	10.00	2.5	-	13.99	-	-	14	3.51	3.51
6	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई)	8.26	-	-	19.4	9.7	9.7	28	17.91	17.91
7	कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ)*	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-
8	सीडीपी	-	-	-	3.45	-	-	3.45	-	-
	कुल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	**580.83**	**318.56**	**312.75**	**414.19**	**205.98**	**205.98**	**544.08**	**378.17**	**378.17**
ख	**कृषोन्नति योजना**									
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	35.45	-	-	42.12	10.53	12.18	52.65	32.91	40.78
10	(एनएमईओ-ओपी)	96.28	-	-	91.01	17.65	-	158.2	98.87	67.87
11	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस)	24.91	-	-	12.00	3.00	0.81	17.9	11.19	11.73
12	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	100.00	50.00	38.48	63.9	24.00	12.00	65.00	51.13	23.79
13	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	13.00	6.5	8.16	8.44	6.33	7.57	10.00	6.25	7.98
14	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	9.00	0.36	0.36	15.3	3.38	3.38	7.64	4.77	4.77
15	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	0.05	-	-	0.1	-	-	0.3	0.19	0.14
16	डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम)	-	-	-	-	5.00	-	29.28	5.92	5.92
	कुल कृषोन्नति योजना	**278.68**	**56.86**	**47.00**	**232.87**	**69.89**	**35.94**	**340.97**	**211.23**	**162.98**

अनुबंध III

कोनासीमा जिले सहित आंध्र प्रदेश में योजनाओं की वास्तविक प्रगति:-

योजनाओं का नाम	**वास्तविक प्रगति**
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	इस योजना के शुभारंभ से, अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 19,901.33 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसमें से 780.14 करोड़ रुपये 22वीं किस्त के दौरान 39,00,681 लाभार्थियों को वितरित किए गए। कोनासीमा जिले में 22 किस्तों के माध्यम से 675.45 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसमें से 22.61 करोड़ रुपये 22वीं किस्त के दौरान 1,13,026 लाभार्थियों को वितरित किए गए।
प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)	इस योजना के शुभारंभ से अब तक आंध्र प्रदेश राज्य में 32,413 किसानों को नामांकित किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)	बीमा कंपनियों ने 5,592 करोड़ रुपये के दावों का निपटान और भुगतान किया है। कोनासीमा जिले में वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 45,507 किसानों को 10.27 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।
एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)	इस योजना के शुभारंभ से, अब तक 3402.19 करोड़ रुपये के ऋण घटक के साथ 5624.09 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 6413 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कोनासीमा जिले में अब तक 81.28 करोड़ रुपये के ऋण घटक के साथ 150.08 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 261 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	इस योजना के शुभारंभ से, अब तक 714 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 23 एफपीओ कोनासीमा जिले में पंजीकृत किए गए हैं।
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)	आंध्र प्रदेश राज्य में 190.06 लाख रुपये की कुल 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
प्रधान मंत्री अन्नदता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक आंध्र प्रदेश राज्य में 1049.97 करोड़ रुपये की लागत से 154471.3 मीट्रिक टन कोपरा, चना, मूंग, तुअर और उड़द की खरीद की गई है, जिससे 97047 किसान लाभान्वित हुए हैं।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)	विगत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में 2,90,643 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। इसमें से 234 हेक्टेयर कोनासीमा जिले में कवर किया गया है।
कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	वर्ष 2014-15 से एसएमएएम योजना के शुभारंभ से, आंध्र प्रदेश राज्य में किसानों को 2,79,515 से अधिक कृषि मशीनें वितरित की गई हैं।
परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई)	पीकेवीवाई योजना (बीपीकेपी कार्यक्रम सहित) के अंतर्गत जैविक खेती के तहत कवर किया गया कुल क्षेत्र 3.61 लाख हेक्टेयर है और 7.47 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)	आंध्र प्रदेश राज्य में 1,63,06,877 के लक्ष्य की तुलना में अब तक कुल 1,58,41,518 सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	वर्ष 2014-15 से आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 69,524 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 123.97 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।
कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक इस योजना के तहत 5,86,803 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	इस योजना के शुभारंभ से, आंध्र प्रदेश राज्य में 6.21 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, और प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय बीज रिजर्व में 2.21 लाख क्विंटल बीज संग्रहीत किए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)	विगत तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में 95,157 हेक्टेयर क्षेत्र डेमोन्सट्रेशन किए गए, 56,417 क्विंटल बीज वितरित किया गया और 32,673 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया है।
एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)	इस योजना के शुभारंभ से, 61.51 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली कुल 1551 भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (गोदामों) को अनुमोदन प्रदान किया गया है और 31936.76 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुल 577 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है और 8603.21 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।
समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक, आंध्र प्रदेश राज्य में 19.96 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले कुल 480 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, 756 मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए हैं, 68 नर्सरी स्थापित की गई हैं और 2.20 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम	इस योजना के शुभारंभ से, आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक 1,12,000 के लक्ष्य की तुलना में 95,945 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन	आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तिलहन के तहत कुल 15.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
डिजिटल कृषि मिशन	आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक कुल 49,340,54 किसान आईडी तैयार किए गए हैं।
राष्ट्रीय बांस मिशन	आंध्र प्रदेश राज्य में 42 हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्र को बांस रोपण के अंतर्गत शामिल किया गया है और 288 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना से विगत 3 वर्षों में 25 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

****